

'नमो भारत' रेल को पीएम ने दिखाई हरी झंडी

देश की पहली रैपिडक्स ट्रेन को पीएम मोदी ने किया रवाना, बोले- यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण



संजय बाटला

'नमो भारत' रेल को पीएम ने दिखाई हरी झंडीपरिवहन विशेष। एसडी सेठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देश की पहली रैपिड रेल 'नमो भारत' ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली वालों के लिए बड़ी सीगत दी।

उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम उसी ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में सफर के दौरान स्कूली बच्चों और क्रूज़ मेम्बर से भी बातचीत की। इस

ट्रेन से शुरू होने से इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी।

बता दें केंद्र सरकार ने इस रैपिड रेल का नाम बदल कर 'नमो भारत' रखने का फैसला किया है। उद्घाटन के बाद इस ट्रेन को आम यात्री भी इस रेल से सफर का आनंद ले सकेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने के पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा। इस कॉरिडोर

की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। जिसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। कल यानि शनिवार से आम यात्रियों के लिए भी सफर शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन में सफर के लिए मिनिमम किराया 20 रुपये निर्धारित किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने मेरठ और दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। दो घंटे का ये सफर सिर्फ 30 मिनट में तय हो सकेगा।

रैपिड एक्स शुभारंभ की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। गाजियाबाद में देश की पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार दे दी है। पीएम मोदी ने रैपिडएक्स ट्रेन में सफर भी किया। रैपिडएक्स को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई जरूरी और बड़ी बातें कही।

पीएम ने आगे कहा, "जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मेरठ वाला हिस्सा 1-1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा।"

पीएम बोले, "अभी मुझे इस आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव प्राप्त हुआ है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है।"

पीएम ने अपने संबोधन में कहा, "यह भारतीय रेल के कायाकल्प का दशक है। आप लोगों को पूरी रेल बदली हुई आएगी, मुझे छोटे सपने व मरते-मरते चलने आदत नहीं है।"

पीएम मोदी ने कहा, "रेलवे जल्द ही 100 प्रतिशत बिजली करण होगा। इसके पहले वन्देभारत, अम्रत भारत नमो भारत की त्रिवेणी पूर भारत की प्रतीक बनेंगी। यातायात के

माध्यमों को जोड़ा जा रहा है। नमो भारत में भी इसका ख्याल रखा गया है कि स्टेशनों पर बस अड्डा मेट्रो व रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है।"

पीएम मोदी बोले, "सार्वजनिक यातायात पर जितना खर्च हो रहा है कभी नहीं हुआ। हम जल, थल और नभ में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा वाटरवोट टर्मिनल काशी से बन रहा है।"

पीएम ने कहा, "21वीं सदी का हमारा भारत आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर दुनिया में छाया हुआ है। आज का भारत G20 का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण, उत्सुकता और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है।"

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, "प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। प्रदेश को 10 करोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली में 800 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू हो गई हैं।"

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "कृषि उत्पादों पर 2014 में गेहूँ एमएसपी 1400 था। अब दो हजार के पार हैं और मसूर की दाल का रेट को दो गुना हो गया है।"

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: भारी पड़ेगी 120 KMPH से ऊपर स्पीड, अब घर पहुंचेंगे चालान, चार दिन में 46 गाड़ी कैद

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली से सटे गुरुग्राम व नूंह जिले होते हुए राजस्थान की सीमा में आने वाली दूरी पर वाहनों के चालान की जिम्मेवारी गुरुग्राम पुलिस की होगी। नेशनल हाइवे अथॉर्टी की ओर से हरियाणा सरकार को लिखे गए पत्र के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम से इसे जोड़ा गया है।

कमिश्नरेंट की ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा है। ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में हरियाणा की सीमा में 16 स्थानों पर लगे 80 कैमरे में चार दिन के भीतर तेज रफ्तार में दौड़ने वाले 46 वाहन कैद हुए हैं। इसमें मर्सिडीज, ऑडी, फरारी एक्सयूबी शामिल हैं। इन सभी के चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से चडीगढ़, गुजराज, हिमाचल व महाराष्ट्र के पते पर ऑनलाइन भेजे गए हैं। वाहन मालिकों की ओर से अगर लगातार तीन पर चालान कटने पर अगर चालान न भुगता गया तो ट्रैफिक पुलिस संबंधित अथॉर्टी को पत्र लिख कर उसके मालिक के वाहन चालाने के लाइसेंस को निरस्त करने की सिफारिश करेगी।

दिल्ली से सटे गुरुग्राम व नूंह जिले होते हुए राजस्थान की सीमा में आने वाली दूरी पर वाहनों के चालान की जिम्मेवारी गुरुग्राम पुलिस की होगी। नेशनल हाइवे अथॉर्टी की ओर से हरियाणा सरकार को लिखे गए पत्र के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम से इसे जोड़ा गया है। कुछ



दिन पहले इसे कंट्रोल रूम से जोड़ने में इसे परेशानी आ रही थी। इस कारण इस मार्ग पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा था। आईजी ट्रैफिक करनाल की ओर से जारी आदेश के बाद हरियाणा की सीमा में होने वाले चालान को भुगतने की जिम्मेवारी गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की होगी।

पूरा बनने के बाद बड़ेगा दबाव

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि अभी इस मार्ग को पूरी तरह से नहीं जोड़ा गया है। जयपुर से लेकर एम गुजरात के अन्य प्वाइंट के कुछ हिस्सों में इसका निर्माण हुआ है। जिस दिन पूरा मार्ग चालू हो जाएगा। उस दिन से वाहनों का दबाव इस पर बढ़ेगा। तेज गति से चलने वाले वाहन ही दुर्घटना का कारण बनेंगे।

रामलीला कार्यक्रमों में लगातार बढ़ रही भीड़ ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी देखकर ही निकलें बाहर

परिवहन विशेष न्यूज

लव-कुश राम लीला समिति श्री धार्मिक लीला समिति और नव श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा माधव दास पार्क और लाल किले के सामने 15 अगस्त पार्क में 15 से 25 अक्टूबर तक छह बजे से तीन प्रमुख राम लीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने कहा है कि 20 अक्टूबर शुक्रवार से तीनों राम लीलाओं में दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

नई दिल्ली। Delhi Traffic Advisory: लव-कुश रामलीला समिति, श्री धार्मिक लीला समिति और नव श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा माधव दास पार्क और लाल किले के सामने 15 अगस्त पार्क में 15 से 25 अक्टूबर तक छह बजे से तीन प्रमुख राम लीलाओं का आयोजन किया जा रहा है।

यातायात पुलिस ने कहा है कि 20 अक्टूबर शुक्रवार से तीनों राम लीलाओं में दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में लोगों को सलाह



दी जाती है कि वे रामलीला स्थल तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का उपयोग करें। यातायात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़क पर यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है।

यातायात परिवर्तन बिंदु

-यदि नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात दबाव बढ़ जाता है तो दरियागंज से नेताजी सुभाष मार्ग

पर आने वाले यातायात को निषाद राज मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा।

छत्ता रेल से लाल किले की ओर आने वाले यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात दबाव होने की स्थिति में सलीमगढ़ बाईपास और महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) पर डायवर्ट किया जाएगा।

-लाल किले के सामने यातायात की स्थिति

को ध्यान में रखते हुए माल वाहक वाहनों और बसों को उपरोक्त अनुसार डायवर्जन की योजना बनाई जाएगी।

-आगतुकों को राम लीला स्थल तक पहुंचने के लिए मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। निकटतम मेट्रो स्टेशन वायलेट लाइन पर लाल किला और जामा मस्जिद और येलो लाइन पर चांदनी चौक और चावड़ी बाजार हैं।

सीएमन्यूएम: दिल्ली-एनसीआर शहरों के बीच सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-VI डीजल बसें चलाने की इजाजत, एक नवंबर से फैसला लागू

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय वायु गुणवत्ता फैनल ने शुक्रवार को एलान किया है कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के भीतर आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस VI-अनुरूप डीजल बसें को चलाने की अनुमति दी जाएगी।

केंद्रीय वायु गुणवत्ता फैनल ने शुक्रवार को एलान किया है कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के भीतर आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस VI-अनुरूप डीजल बसें को चलाने की अनुमति दी जाएगी।

इस उपाय का मकसद क्षेत्र में चलने वाली डीजल से चलने वाली बसों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से निपटना है। जिसका अंतिम लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करना है।

यह घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा की गई है।

प्रदूषण के स्तर को कम करने के प्रयास में, केंद्र ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि भारत में बेचे जाने वाले सभी वाहनों को भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा।

भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) जैसे



वायु प्रदूषकों की मात्रा पर कानूनी सीमा निर्धारित करते हैं, जो भारत में वाहन उत्सर्जित कर सकते हैं। ये मानक उत्सर्जन नियंत्रण, ईंधन दक्षता और इंजन

डिजाइन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चूंकि वाहन निर्माता इन नए मानकों को पूरा करने वाले वाहन प्रदान करते हैं, तेल कंपनियां

बीएस-VI मानकों का पालन करने वाले ईंधन की आपूर्ति करती हैं, जिसे दुनिया के सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है।

टैपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दंतेश्वरी फाइटर्स - बस्तर में माओवादियों से लोहा लेती वीरांगनाएं

दंतेश्वरी फाइटर्स के विभिन्न अभियानों की बात करें तो बीते 4 वर्षों में इनका सामना 70 से अधिक बार माओवादियों से हुआ है। इन मुठभेड़ों में दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने 10 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है।

छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित बस्तर क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ दंतेवश्वरी के नाम पर बस्तर पुलिस ने वर्ष 2019 में दंतेश्वरी फाइटर्स का गठन किया था, जिसमें महिला कमांडो पदस्थ हैं। ये महिला कमांडोज घने जंगलों, नदियों एवं पहाड़ों के बीच ना सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि माओवादी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं।

नारी शक्ति का यह रूप नवरात्रि के दौरान भी दिखाई दे रहा है, जब दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाएं नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए विभिन्न अभियान चला रही हैं। बस्तर के धुर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात इन लड़ाकू महिलाओं में से अधिकांश विवाहित हैं, और बावजूद इसके वो अपनी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं।

यदि दंतेश्वरी फाइटर्स के विभिन्न अभियानों की बात करें तो बीते 4 वर्षों में इनका सामना 70 से अधिक बार माओवादियों से हुआ है। इन मुठभेड़ों में दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने 10 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है।

गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, और बस्तर के माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी सुरक्षा की कमान इन दंतेश्वरी फाइटर्स के हाथ में भी होगी। बस्तर में चुनाव के दौरान महिला कमांडो को पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की कमान सौंपी जाएगी।

दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने बीते 4 वर्षों में विभिन्न अभियानों में भी हिस्सा लिया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी का कहना है कि दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडोज माओवादियों से लोहा तो लेती ही हैं, साथ ही ग्रामीणों की देखभाल और उनकी सहायता का कार्य भी करती हैं।

पुलिस आईजी के अनुसार इस समूह में कुल 60 लोगों में से 10 ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो पूर्व में माओवादी संगठन का हिस्सा रह चुकी हैं और आत्मसमर्पण करने के बाद मुख्यधारा में लौटी हैं।

दंतेश्वरी फाइटर्स के महिला कमांडोज की



विशेष ट्रेनिंग हुई है ताकि विपरीत परिस्थितियों में माओवादियों का मुकाबला किया जा सके, इसके अलावा इन महिला कमांडोज के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

ग्रामीण महिलाओं को साफ-सफाई के बारे में जानकारी देने से लेकर बीमार पड़ने में उनके प्राथमिक उपचार के लिए दवाई उपलब्ध कराने तक की सहायता दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं के द्वारा की जा रही है।

दंतेश्वरी फाइटर्स द्वारा चलाए गए कुछ अभियानों की बात करें तो इसमें माओवादी स्मारक को ध्वस्त करने से लेकर माओवादियों के साथ मुठभेड़ और माओवादी आतंक के चलते प्रभावित कार्यों को पुनः आरंभ कराना भी शामिल है।

दंतेश्वरी फाइटर्स की वीरांगनाओं ने दंतेवाड़ा के भीतरी ग्रामीण क्षेत्र में बने माओवादी स्मारक को ध्वस्त करने का अभियान चलाया था। यह माओवादी स्मारक लाख रुपये की इनामी महिला माओवादी भीमे उर्फ आयते के नाम पर बना था, जिसकी स्मारक तोड़ने से 2 माह पूर्व ही सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी।

माओवादियों ने स्थानीय ग्रामीणों पर दबाव डालकर यह स्मारक बनवाया था, जिसे तीन वर्ष पूर्व महिला दिवस के दिन दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला योद्धाओं ने ध्वस्त कर दिया था। स्मारक को ध्वस्त करने के बाद सुरक्षा बल की महिलाओं का कहना था कि वो अपने कार्य पर हैं और कर्म ही उनकी पूजा है।

इसके अलावा जब सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित नहाड़ी गांव में सुरक्षाबलों का कैप स्थापित किया जा रहा था तब भी माओवादियों ने इसमें काफी अड़चन डालने का प्रयास किया था।

दरअसल यह क्षेत्र 10-10 लाख रुपये के इनामी माओवादी आतंकी कमांडर देवा और विनोद का गांव था, जो माओवादियों के छिपने के लिए उपयुक्त स्थान हुआ करता था। सुरक्षाबलों ने जब इस स्थान में कैप बनाने का निर्णय किया तब माओवादियों ने स्थानीय ग्रामीणों को भड़काकर एवं धमकाकर आंदोलन भी शुरू करवा दिया।

माओवादियों के द्वारा भड़काए जाने के बाद ग्रामीण पोस्टर-बैनर लेकर कैप का विरोध करने लगे। लेकिन इसके बाद दंतेश्वरी फाइटर्स की

वीरांगनाओं ने मोर्चा संभाला और सफल भी हुए। महिला कमांडोज ने स्थानीय ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को विश्वास में लिया और उन्हें कैप खुलने के बाद के लाभों की जानकारी दी।

इस अभियान के बारे में दंतेश्वरी फाइटर्स से जुड़ी एक महिला अधिकारी ने बताया था कि उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन महिला कमांडोज ने हार नहीं मानी और अपने विश्वास पर अडिग रहे, यही कारण है कि फरवरी 2022 में यह कैप खुल पाया।

इस दौरान माओवादियों ने भी महिला कमांडोज पर हमले किए, आपसी मुठभेड़ हुए जिसमें महिलाओं ने 2 माओवादियों को मार गिराया था। सिर्फ आक्रामक अभियानों या मुठभेड़ों के मामले में ही नहीं, बल्कि स्थानीय कलाओं के माध्यम से भी दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया है।

दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने बस्तर की संस्कृति परंपरा के अनुसार गोंडी और हल्बी नृत्य करते हुए माओवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा से जुड़ने का संदेश दिया

था।

इसके अलावा दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाएं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाते हुए ग्रामीणों से संपर्क करती हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करती हैं और साथ ही उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी बेसिक व्यवस्थाओं में सहायता करती हैं, यही कारण है कि ग्रामीणों के भीतर भी अब दंतेश्वरी फाइटर्स को लेकर विश्वास की भावनाएं बढ़ रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर महिलाओं में दंतेश्वरी फाइटर्स की उपस्थिति, उनकी बढ़ती विश्वसनीयता और उनके द्वारा माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों से माओवादी भी डरे हुए हैं। माओवादियों ने पंचे फेंककर स्थानीय ग्रामीण युवतियों एवं महिलाओं को दंतेश्वरी फाइटर्स में शामिल ना होने की चेतावनी जारी की थी।

इन चेतावनियों से स्पष्ट समझा जा सकता है कि माओवादी दंतेश्वरी फाइटर्स की कार्य शैली और रणनीतियों से बुरी तरह घबराए हुए हैं और ग्रामीणों के बीच उनकी प्रसिद्धि से माओवादियों की तिलमिलाहट भी नजर आ रही है।

इस अभियान के बारे में दंतेश्वरी फाइटर्स से जुड़ी एक महिला अधिकारी ने बताया था कि उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन महिला कमांडोज ने हार नहीं मानी और अपने विश्वास पर अडिग रहे, यही कारण है कि फरवरी 2022 में यह कैप खुल पाया।

कभी जंगल था बसेरा, आज रैंप पर थिरकते हैं आत्मविश्वास से भरे कदम, वनटांगिया महिलाएं हैं प्रेरणा की मिसाल



वनटांगिया महिलाएं लिख रही हैं बदलाव की कहानी

वनटांगिया महिलाओं का लंबा लेकिन सफल सफर जो प्रेरणादायक है, के पीछे की कहानी दिलचस्प है। आज ये महिलाएं फैशन शो में रैंप पर चल रही हैं जबकि कभी बकरी चराती थीं, कोई खेती तो कोई सब्जी बेचने का काम करती थीं।

जिनकी पहचान ही जंगलों तक सिमट गई थी, उनको राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों में रैंप पर जलवा बिखरते देखने की बात अचरज में डालती है। जो जंगल में बसे अपने गांव में ही सकुचाई सी रहती थीं, आज फैशन व संस्कृति शो में उनके कदम आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ते हैं। वास्तव में इस आश्चर्यजनक सत्य के पीछे योगी सरकार की

मिशन शक्ति की प्रेरणा है।

नारी स्वावलंबन और सम्मान के लिहाज से बदलाव की यह दास्तां है गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल लिकोनिया नंबर तीन की। कभी झुगियों में रहने को ही जिन वनटांगिया महिलाओं व युवतियों ने अपनी नियति मान लिया था, आज उनका जलवा फैशन शो के रैंप तक नजर आता है। जनवरी 2022 से अब तक गोरखपुर महोत्सव, आगरा महोत्सव, अयोध्या के सावन झूला महोत्सव, मथुरा, काशी में जी-20 समारोह व महाराजगंज महोत्सव में आयोजित फैशन व संस्कृति शो में वनटांगिया महिलाओं ने शानदार प्रतिभागिता से यह सबित कर दिखाया है कि मौका मिलने पर वे किसी से कमतर नहीं हैं। वनटांगिया महिलाओं व युवतियों को फैशन शो के रैंप तक का सफर कराया है गोरखपुर में पैदा हुई राजस्थान मूल की सुगम सिंह शेखावत ने। सुगम की आश्चर्यजनक सत्य के पीछे योगी सरकार की

है और वह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। सुगम सिंह शेखावत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से कभी वंचितों में गिने जाने वाले वनटांगिया समाज की जिंदगी में आए व्यापक परिवर्तन की मुरीद हैं। उनका कहना है कि फैशन व संस्कृति शो में प्रतिभाग कराकर वह वनटांगिया नारियों को आगे बढ़ाने की सीएम योगी की सोच व उनके द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति से खुद को जोड़ रही हैं। फैशन शो में रैंप पर चलने वालों में कोई बकरी चराती थीं, कोई खेती तो कोई सब्जी बेचने का काम, सुगम उन्हें प्रशिक्षित कर रैंप तक ले आई हैं। इन्होंने कभी स्ट्रेज तक नहीं देखा था, आज 17 साल की किशोरी से लेकर 66 वर्ष की बुजुर्ग तक रैंप पर सम्मान बटोर चुकी हैं।

वनटांगिया महिलाओं ने अब तक जितने भी फैशन शो किए, वे सब भारतीय संस्कृति के थीम पर रहे हैं। इसका सिलसिला शुरू हुआ गोरखपुर महोत्सव 2022 से जिसके शो

स्टॉपर थे फ़िल्म अभिनेता व सांसद रविकिशन, फिर तो आगरा महोत्सव, अयोध्या, मथुरा में भी उनके कदम आत्मविश्वास से आगे बढ़ते गए। काशी में जी-20 के समारोह में विदेशी मेहमान भी उनके कायल हो गए, सुगम सिंह शेखावत बताती हैं कि हर आयोजन में लोगों को यह भी जानकारी दी जाती है कि वनटांगिया लोगों की पहले जिंदगी कैसी थी और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदलाव आया।

बता दें कि दशकों तक उपेक्षा ही वनटांगियों की पहचान बनी हुई थी। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इनके जीवन में भी विकास की दस्तक हुई। बुनियादी सुविधाओं से संतुप्त होकर वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। आवास, बिजली, पानी, चूल्हा, राशन, पेशन, सड़क, खेत की चिंताओं से उपर उठकर अब बड़ा सपना देख रहे हैं।

गर्भवती महिलाएं किस तरह रखें नवरात्रि व्रत? डाइटिशियन ने बताए 5 टिप्स, सेहत नहीं होगी खराब



15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाएगा. नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है. इसलिए बड़ी संख्या में लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं. हालांकि गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए, वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती है.

अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना कहा जा सकता है. इस महीने में तमाम व्रत और त्योहार मनाए जा रहे हैं. अब 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी. हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र और मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है. नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखना भी आम बात है. बड़ी संख्या में लोग इन दिनों में व्रत रखकर पूजा-अर्चना करते हैं. शारदीय नवरात्रि में मौसम ठंडा होने लगता है और इस दौरान मौसमी फल का कहर बढ़ जाता है. ऐसे में व्रत रखते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि सेहत खराब न हो

कई गर्भवती महिलाएं भी नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखती हैं. हालांकि प्रेग्नेसी में लंबे समय तक कुछ न खाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका रहती है. इसलिए हम तो यह सलाह देंगे कि यदि संभव हो तो व्रत न रखें. लेकिन

श्रद्धावश रखना ही है तो व्रत के दौरान बेहद सावधानी बरतें. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो व्रत रखना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक व्रत रखना हो, तो समय-समय पर हेल्दी फूड्स का सेवन करना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए. व्रत के दौरान कुछ भी न खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आज आपको बताएंगे कि 9 दिनों तक व्रत रखने का सही तरीका क्या होता है और गर्भवती महिलाएं व्रत में कैसी डाइट लें.

क्या गर्भवती महिलाओं को रखना चाहिए व्रत ?

नोएडा के डाइट मंत्रा की फाउंडर और डाइटिशियन कामिनी सिन्हा के मुताबिक नवरात्रि में व्रत रखने से बांड़ी डिटॉक्स होती है और आंत रिलैक्स हो जाती हैं. इससे शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन व्रत के दौरान भूखा नहीं रहना चाहिए. व्रत वाली खाने-पीने की चीजों का सही तरीके से सेवन करना चाहिए. व्रत के दौरान लंबे समय तक भूखा रहने से एसिडिटी, वीकनेस और सिरदर्द की परेशानी हो सकती है. व्रत में पर्याप्त पानी न पीने की वजह से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे बचने की जरूरत होती है. व्रत में कुछ न खाने से माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है. प्रेग्नट महिलाओं को नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत रखने से बचना चाहिए. लंबे समय तक भूखा रहने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है. अगर गर्भवती महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं, तो उन्हें पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. बिना डॉक्टर की सलाह हो तो व्रत न रखना

दिल्ली में ठंड का दौर शुरू, औसत से दो डिग्री कम राजधानी का न्यूनतम तापमान

परिवहन विशेष न्यूज

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान औसत से दो डिग्री से कम रहा है। शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंड सुबह रही है। बीते 13 वर्षों में भी 19 अक्टूबर को इतना कम न्यूनतम तापमान नहीं रहा।

नई दिल्ली। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी के चलते दिल्ली के तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है तापमान में गिरावट के चलते अब राजधानी में ठंडक का असर देखने को मिल रहा है।

औसत से दो डिग्री कम तापमान

शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान औसत से दो डिग्री से कम रहा है। शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंड सुबह रही है। खास बात है कि बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं, बल्कि बीते 13 वर्षों में भी 19 अक्टूबर को इतना कम



न्यूनतम तापमान नहीं रहा। मौसम के साफ रहने का अनुमान लगाया है। शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है। शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

(सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 10 बजे के आसपास 260 रहा।

दिल्ली की कोर्ट में IRTC घोटाले को लेकर हुई सुनवाई, तेजस्वी यादव-राबड़ी देवी की तरफ से छह नवंबर को रखी जाएंगी दलीलें

रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े आइआरसीटीसी घोटाले में शुक्रवार को सह-आरोपित कंपनी लारा प्रोजेक्ट एलएलपी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश की। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपित की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई में तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी की तरफ से दलील रखने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े आइआरसीटीसी घोटाले में शुक्रवार को सह-आरोपित कंपनी लारा प्रोजेक्ट एलएलपी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश की। इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहें।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपित की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई में



तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी की तरफ से दलील रखने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई छह नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है। इसके पहले सह-आरोपित सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता की तरफ से दलील रखी गई थी।

सीबीआई के आरोपपत्र को लेकर हो रही है सुनवाई

अदालत सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही

है। सीबीआई ने आरोप पत्र में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू भारत के रेल मंत्री रहे उस समय रेलवे बोर्ड ने विभागा के सभी होटलों और ट्रेनों में कैंटरिंग सेवा आइआरसीटीसी को सौंप दिया था। इसी दौरान झारखंड के रांची और उड़ीसा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई।

पतंजलि-OLA जैसी नामचीन कंपनियों की बनाई फर्जी वेबसाइट, तीन साल तक ठगी कर कमाए पांच करोड़ ; दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़

पतंजलि-ओला समेत कई नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर तीन साल में लोगों से पांच करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का स्पेशल स्टाफ ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना दिल्ली के सुलेमान नगर निवासी राजा उर्फ साहिल सुल्तानपुरी निवासी विकास व मोहम्मद सुहैल अंसारी किराड़ी अंकित यादव बिहार के नालंदा निवासी कन्हैया महतो बिहारी पासवान उर्फ उदय इसके भाई अजीत पासवान के रूप में हुई है।

नई दिल्ली। पतंजलि व ओला समेत कई नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर तीन साल में लोगों से पांच करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का स्पेशल स्टाफ ने भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने गिरोह के सरगना दिल्ली के सुलेमान नगर निवासी राजा उर्फ साहिल, सुल्तानपुरी निवासी विकास व मोहम्मद सुहैल अंसारी, किराड़ी अंकित यादव, बिहार के नालंदा निवासी कन्हैया महतो, बिहारी पासवान उर्फ उदय इसके भाई अजीत पासवान के रूप में हुई है।

देशभर में दर्ज हैं 67 केस

पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल, सौ

फर्जी सिम, तीन लैपटॉप व पांच एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दक्षिणी राज्यों में आरोपितों के खिलाफ 67 केस दर्ज हैं। 2100 शिकायतें केंद्र सरकार की पॉर्टल पर दर्ज मिली। पहली बार गिरोह के बदमाश पुलिस के हथ्थे चढ़े हैं।

पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने बताया कि विजय यादव नाम के एक व्यक्ति ने सात अक्टूबर को साइबर थाने में ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित को ओला की स्कूटी खरीदी थी। उन्होंने गूगल पर मिली वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया।

ठगों ने पंजीकरण के नाम पर उनसे आनलाइन सवा लाख रुपये ठग लिए।

अन्य भी आफर पर बेचे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह कि नरेला में स्थित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 777 घर बिक चुके हैं।

डीडीए फ्लैट पाने का शानदार मौका, 'पहले आओ-पहले पाओ' के तहत बिके अब तक इतने घर

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में डीडीए फ्लैट पाने का शानदार मौका है। उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष वीके सक्सेना के हस्तक्षेप और प्रयासों का प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि 100 दिनों में ही डीडीए की 'पहले आओ-पहले पाओ' आवास योजना के तहत 5623 में से 2234 फ्लैट बिक चुके हैं। ऐसे में बाकी फ्लैट को खरीदने का शानदार मौका है।

नई दिल्ली। लंबे समय से बिकने में नहीं आ रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैट अब बिकने लगे हैं। उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष वीके सक्सेना के हस्तक्षेप और प्रयासों का प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि 100 दिनों में ही डीडीए की 'पहले आओ-पहले पाओ' आवास योजना के तहत 5623 में से 2234 फ्लैट बिक चुके हैं।

अन्य भी आफर पर बेचे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह कि नरेला में स्थित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 777 घर बिक चुके हैं। डीडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं में कई मौकों पर बिक्री की पेशकश के बावजूद, सभी तरह से पूर्ण और कब्जे के लिए

तैयार ये घर 2011-12 से ही बिना बिके पड़े थे। एलजी ने इसके लिए मानदंडों में बदलाव सुनिश्चित किया, जिससे इच्छुक नागरिकों के लिए फ्लैट खरीदना आसान हो गया। उनके आदेश पर डीडीए की नीतियों में जो परिवर्तन हुए, वह निम्नलिखित हैं:-

दिल्ली में घर मालिकों को डीडीए आवासीय योजनाओं में दूसरा घर खरीदने से रोकने वाली मौजूदा सीमा को हटाकर मानदंडों को आसान बनाना। अब खरीदार इसके बावजूद कि उनके नाम पर पहले से ही पंजीकृत घर है, वह घर खरीद सकते हैं।

पहले की नीति, जब फ्लैटों को लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जाता था, से उलट खरीदार के साइट पर जाने और अपनी पसंद का फ्लैट चुनना सुनिश्चित किया गया। यह निर्णायक साबित हुआ।

पहले फ्लैटों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाता था, और खरीदार को यह देखने का मौका भी नहीं मिलता था कि वह कौन सी संपत्ति खरीद रहे हैं। इससे खरीदार के पास कोई विकल्प नहीं होता था और उसे ऐसी स्थिति में मजबूर होना पड़ता जो उसकी पसंद के अनुरूप नहीं थी।

उपराज्यपाल का विचार था कि घर खरीदना किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए जीवन की बड़ी घटना है। जबर्दस्ती किसी भी संपत्ति को उसके लिए जी का जंजाल नहीं बनाया जा सकता है। सक्सेना ने डीडीए से कहा कि खरीदार को संपत्ति खरीदने से पहले उसे देखना जरूरी है।

डीडीए के विरोध के बावजूद, ईडब्ल्यूएस के लिए बुकिंग राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये, एमआइजी के लिए 2,00,000/- रुपये से 4,00,000/- रुपये और एचआइजी श्रेणी के घरों के लिए 2,00,000/- रुपये से 10,00,00,00/- रुपये की गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल उचित खरीदार ही डीडीए से संपर्क करें और बाद में पीछे न हटें।

उपराज्यपाल ने यह सुनिश्चित किया कि फ्लैट वित्त वर्ष 2022-23 के आधार पर संशोधित मूल्य निर्धारण के बजाय पुरानी दर पर बेचे जाएं।

एक मंजिल पर बने साथ-साथ के फ्लैटों के एकीकरण की अनुमति दी गई, जिससे इच्छुक खरीदारों को प्रोत्साहन मिला।



भुगतान अनुसूची जो पहले प्रारंभिक आवंटन के बाद छह महीने तक बढ़ जाती थी, उसे घटाकर केवल दो महीने कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन संपत्तियों से जो अब तक गैर-

स्टेशन, अस्पताल का निर्माण, नए डीटीसी मार्गों को शुरू करने, मेट्रो कनेक्शन के लिए आगे का रास्ता साफ करने और विश्वविद्यालय परिसरों, अदालत परिसरों की स्थापना आदि के माध्यम से लगातार प्रयास किए गए, जिससे फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों की भावनाओं को बल मिला।

मालूम हो कि कार्यभार संभालने के बाद शुरुआती दिनों में, सक्सेना ने डीडीए की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद, पूंजी के प्रीमियम प्लानर और बिल्डर की खराब वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। साथ ही अधिकारियों को पूरी तरह से सुधार/वसूली मोड पर जाने कहा था।

डीडीए ने 13,782 फ्लैटों की अपनी पुरानी सूची में से, जो बार-बार प्रयासों के बाद भी बिना बिके रह गई थी, मौजूदा योजना में 5623 फ्लैटों को बिक्री के लिए रखा था, जिनमें से 2036 फ्लैट पहले ही बेचे जा चुके हैं। 2236 में से 1249 फ्लैटों का पूरा भुगतान पहले ही प्राप्त हो चुका है और शेष प्रक्रिया में हैं। डीडीए को अब तक कुल 506.04 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है।

पिंकी ईरानी को मिली जमानत, HC ने कहा- आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं

200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी पिंकी ईरानी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि इरानी के आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अदालत ने नोट किया कि 52 वर्षीय इरानी नवंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं।

नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी पिंकी ईरानी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि इरानी के आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अदालत ने नोट किया कि 52 वर्षीय इरानी नवंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। पीठ ने कहा कि यह अदालत मानती है कि मकोका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुकदमे के दौरान आरोपों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यह भी जांच का विषय है कि क्या इरानी द्वारा प्राप्त धन अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए था।

अदालत ने रखी ये शर्त

अदालत ने निर्देश दिया कि इरानी किसी भी परिस्थिति में संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी। पांच लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर जमानत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि इरानी मामले से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी देने की कोशिश नहीं करेंगी।

सुंबई निवासी इरानी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी किया था और इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईओडब्ल्यू ने निचली अदालत के समक्ष दायर अपने पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि इरानी ने चंद्रशेखर को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकिलिन फर्नांडीज से मिलवाया और सुकेश द्वारा की गई 200 करोड़ रुपये की ठगी को ठिकाने लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोपपत्र में आरोप लगाया गया कि इरानी, चंद्रशेखर को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करती थी और कुछ बॉलीवुड हस्तियों के साथ उनकी मुलाकातें कराने में सहायक रही थी।

25 करोड़ के बाद दिल्ली में अब 70 लाख की चोरी, सोने-चांदी के गहने और नकदी लेकर बदमाश फरार

दिल्ली में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोगल में 25 करोड़ की चोरी के बाद लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। अब अमर कालोनी में 70 लाख रुपये की चोरी की घटना सामने आई है। जिस समय चोरी की घटना हुई उस समय परिवारवाले अमृतसर गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोगल में 25 करोड़ की चोरी के बाद लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामले में अमर कालोनी के संत नगर में बदमाशों ने 70 लाख रुपये की चोरी को अंजाम दिया है।

10 लाख नकद भी चोरी

बदमाशों ने बंद घर से 60 लाख रुपये के गहने और 10 लाख नकद चोरी कर लिया। पीड़ित परिवार के लौटने पर मामले की सूचना पुलिस को दी। अमर कालोनी थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।



अमृतसर गया था परिवार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित केदार प्रसाद अपने परिवार के साथ संत नगर, ईस्ट आफ कैलाश में रहते हैं। केदार गद्दी गांव में मीट शाप चलाते हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित ने बताया कि 17 अक्टूबर को पीड़ित अपने परिवार के साथ अमृतसर,

पंजाब गया था। 19 अक्टूबर को परिवार जब वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं।

CCTV खंगाल रही पुलिस

जांच करने पर पता चला कि घर से पीड़ित की पत्नी और मां के नकद और गहने चोरी हुए हैं। पीड़ित के अनुसार उनके घर से करीब 50 लाख रुपये का

सोना, 10 लाख नकद और करीब 10 लाख की चांदी चोरी हुई है। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपितों की पहचान का प्रयास कर रही है।

दिल्ली में MCD स्कूल के पास मिला महिला का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका

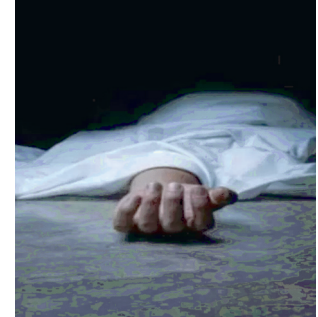
दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एमसीडी स्कूल की दीवार के पास एक महिला का शव मिला है। शुरुआती शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला लग रहा था इसलिए फॉरेंसिक और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। डीडीयू अस्पताल के डॉक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एमसीडी स्कूल की दीवार के पास एक महिला का शव मिला है। शुरुआती जांच में महिला का हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, थाना तिलक नगर में एमसीडी स्कूल की दीवार, तिलक नगर

के पास एक शव पड़े होने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया एक महिला का शव पड़ा मिला।

शुरुआती शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला लग रहा था, इसलिए फॉरेंसिक और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद के लिए डीडीयू अस्पताल के डॉक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया।



रैपिड एक्स ट्रेन के उद्घाटन पर विद्यार्थियों से PM मोदी ने कही यह बड़ी बात, इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए भी मांगे सुझाव

परिवहन विशेष न्यूज़

रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा कि जो सफर एक घंटे में तय होता था अब वह दूसरी नमो भारत रैपिड ट्रेन से केवल 15 मिनट में पूरी होगी। हम आपके समय को बचा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप भी अपने समय का सदुपयोग करें और मोबाइल चलाने में समय बर्बाद न करें।

गाजियाबाद। जो सफर एक घंटे में तय होता था, अब वह दूसरी नमो भारत रैपिड ट्रेन से केवल 15 मिनट में पूरी होगी। ट्रैफिक व पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। हम आपके समय को बचा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप भी अपने समय का सदुपयोग करें और मोबाइल चलाने में समय बर्बाद न करें।

मोबाइल पर गेम खेल रही थी किशोरी, फिर हुआ कुछ ऐसा...हो गई मौत

गाजियाबाद के विजयनगर स्थित चांदमारी कालोनी में रहने वाले राजेश की 17 वर्षीय बेटी बबीता मोबाइल पर गेम खेल रही थी। इस दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। बेहोशी की हालत में बबीता को उसके भाई सविन ने जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया।

गाजियाबाद। विजयनगर स्थित चांदमारी कालोनी में रहने वाले राजेश की 17 वर्षीय बेटी बबीता की शुक्रवार सुबह को हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वह मोबाइल पर गेम खेल रही थी। बेहोशी की हालत में बबीता को उसके भाई सविन ने जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया।

हार्ट अटैक को लेकर डॉक्टर ने कही ये बात

सीएमएस डा. मनोज कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को अंतिम संस्कार के लिए हरदोई (घर) ले गए। राजेश मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं। इमरजेंसी में सबसे पहले बबीता की जांच करने वाले डॉ. आलोक ने बताया की इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आने का कारण खराब दिनचर्या और खानपान है।

चिकित्सक के पृछताछ में पता चला की किशोरी तला भुना अधिक खाती थी और शारीरिक मेहनत नहीं करती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर तनाव में रहती थी। पहले से कोई बीमारी नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि बदलती दिन चर्या और खानपान का ही असर है कि हंसते-खेलते, टटलते, जिस करते और नाचते-गाते युवाओं के

इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए मांगे सुझाव

हफ्ते में एक दिन नो मोबाइल डे मनाएं। यह बात नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों से कही। प्रधानमंत्री ने आरकेजीआइटी के बीटेक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों से नमो भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे। कहा कि वह नमो भारत की प्रथम यात्रा पर एक रिपोर्ट बनाकर भेजें। जिसे वह स्वयं पढ़ना चाहते हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि उनका प्रधानमंत्री के साथ अनुभव बहुत ही सहज और अच्छा रहा। नरेन्द्र मोदी ने सवाल किया कि वह कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं तो विद्यार्थियों ने बताया कि पांच से छह घंटे, तो पीएम ने उन्हें मोबाइल में समय बर्बाद न करने की सलाह दी।

देश में ला रहे 500 और रैपिड ट्रेन-पीएम मोदी

उन्होंने मोबाइल प्रयोग को घर में केवल एक जगह निर्धारित करने के लिए कहा। पीएम ने बताया कि वह देश में 500



और रैपिड ट्रेन ला रहे हैं। इसके साथ ही अपने 40 मिनट के संबोधन के अंत में पीएम ने लोगों से कहा कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप अपनी साइकिल और स्कूटर भी संभालकर रखते हैं। यह ट्रेन आपकी है।

आज वादा कीजिए कि आप सभी नमो भारत ट्रेन को एक खरोंच भी आने नहीं देंगे। पीएम ने कहा कि ट्रेन साफ-स्वच्छ और सुरक्षित रहे, यह आपकी जिम्मेदारी है। पीएम का यह कहना इसलिए अहम है,

क्योंकि एक तो आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के मामले सामने आए हैं और दूसरे, आम तौर पर लोग आधुनिक फीचरों से लैस ऐसे साधनों के रखरखाव के प्रति लापरवाही का भी प्रदर्शन करते हैं।

नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन से पहले बनाई आधी-अधूरी सड़क, अपनी नाकामी छुपाने में अधिकारियों ने दिखाई हड़बड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर को सेमी हाईस्पीड आधुनिक नमो भारत ट्रेन के पहले भाग का उद्घाटन कर दिया है। रैपिड ट्रेन नमो भारत का आरंभ कर गाजियाबाद के विकास को रफ्तार दी है। मगर जमीन से कई फीट ऊंचाई पर दौड़ रही ट्रेन के ठीक नीचे गड्ढे अधबनी सड़क इसकी खूबसूरती पर बदनुमा धब्बे की तरह दिख रहा है।

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रैपिड ट्रेन नमो भारत का आरंभ कर गाजियाबाद के विकास को रफ्तार दी है। मगर जमीन से कई फीट ऊंचाई पर दौड़ रही ट्रेन के ठीक नीचे गड्ढे, अधबनी सड़क और झुगियां बसाकर किया गया अतिक्रमण इसकी खूबसूरती पर बदनुमा धब्बे की तरह दिख रहा है।

केंद्र की मोदी सरकार नए-नए प्रोजेक्ट से यूपी के द्वार गाजियाबाद को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है तो वहीं ये धब्बे स्थानीय प्रशासन के निकम्मेपन की गवाही दे रहे हैं।

सुरक्षा में मुस्तेदी, व्यवस्था में सुस्ती

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस व प्रशासन ने तमाम दावे किए। रूट और संभावित रूट के चपे-चपे पर सुरक्षा में मुस्तेद दिखे, लेकिन प्रशासन प्रधानमंत्री के गाजियाबाद पहुंचने के बाद भी व्यवस्था पूरी नहीं



कर पाया। रैपिड ट्रेन के गुलधर स्टेशन से गुलधर गेट तक रातों-रात सड़क पर छोटी बजरी बिछाई गई, लेकिन वह भी आधी अधूरी। तीन लेन में से कहीं दो तो कहीं एक ही लेन पर यह परत डाली गई।

यह लापरवाही आने वाले दिनों में हादसे का सबब बन सकती है। सड़क किनारे पड़ा कूड़े और सड़ रहे पानी पर साढ़े 10 बजे तक मिट्टी डालने का काम चल रहा था। यहां तक कि मेरठ रोड पर 11 बजे तक चूना छिड़का गया और इस दौरान कर्मचारियों के साथ वाहन चालकों की जान को भी खतरे में डाला गया। यातायात के बीच बिना बैरियर काम कराया जा रहा था।

पानी निकालाना मिट्टी हटाई

मेरठ तिराहा पर जमीनी सड़क, फ्लाइओवर, मेट्रो और रैपिड ट्रेन का ट्रैक एक साथ दिखते हैं और राज नगर एक्सटेशन चौहारा पर भी सड़क, फ्लाइओवर और रैपिड ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है। बावजूद इसके जमीन पर न पानी की निकासी है, न सड़क सुरक्षा। हैरानी इस बात की है कि पीएम के रैपिड ट्रेन से यहां गुजरने के पूर्व तय कार्यक्रम के बाद भी यहां के गड्ढे नहीं भरे गए। सड़क किनारे जमा पिछले दिन हुई वर्षा का पानी और मिट्टी भी नहीं हटाई गई।

किसकी शह पर बर्सीं झुगियां

गुलधर गेट व गुलधर स्टेशन के बीच शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले मेरठ रोड किनारे जमीन पर कब्जा कर झुगियां डाल ली गई थीं। बीते दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने झुगियां हटा दी थीं, लेकिन यात्रा के समापन के बाद ये फिर अपनी जगह पर आ गईं।

सवाल है कि वाहन चालकों और झुगियों में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चों की जान के लिए खतरा बनीं ये झुगियां किसकी शह पर दोबारा बसाई गईं। इन्हें दोबारा बसने से रोका क्यों नहीं गया। सवाल यही है कि यदि प्रधानमंत्री वापसी में सड़क मार्ग से आने को कहते तो अधिकारी अपनी नाकामी कैसे छिपाते।

गुज्जर और गोजरी भाषा व मजहब का सवाल

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

दरअसल पाकिस्तान सरकार वहां की स्थानीय भाषाओं को समाप्त करने का प्रयास करती रहती है। वहां गोजरी की स्थिति ठीक नहीं है। गुज्जर जिसे संस्कृत में गुर्जर कहा जाता है, जितना प्राचीन शब्द है, उतना ही प्राचीन इनका इतिहास है। गुजरात और राजस्थान से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में जितने गुज्जर समुदाय के लोग हैं, वे सभी किसी न किसी समय राजस्थान से ही चल कर इन स्थानों पर पहुंचे थे। मोटे तौर पर गुज्जर पशुओं का पालन करते हैं। उनको लेकर निरन्तर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। लेकिन इतने वर्षों में गुज्जर जन-धूमदाय के कुछ लोगों ने घुमक्कड़ी का जीवन छोड़ कर स्थायी तौर पर भी रहना शुरू कर दिया है। स्थायी तौर पर रहने वाले गुज्जरों को मुकामी गुज्जर भी कहा जाता है। मुकामी गुज्जर जरूरी नहीं कि पशुपालन का धन्धा ही करते हों। वे अन्य व्यवसायों में भी चले गए हैं। जम्मू और कश्मीर में जो गुज्जर बकरियों का पालन करते हैं, उन्हें बकरवाल भी कहा जाता है। जो गुज्जर वनों में रहकर गाय-भैंस का पालन करते हैं, उन्हें वनगुज्जर या बनिहारा गुज्जर भी कहा जाता है। गुज्जर अपनी वंश परम्परा भागवान कृष्ण से जोड़ते हैं क्योंकि वे भी गोपालक कहे जाते हैं। गुज्जरों के लोकगीतों में भी अनेक जगह इसका जिक्र आता है। जम्मू कश्मीर में गुज्जरों की जनसंख्या 1941 की जनगणना के अनुसार 381457 थी। 1951 में जम्मू कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं हो सकी। 1961 में जनगणना तो हुई लेकिन उसमें गुज्जरों को प्रदेश के अन्य मुसलमानों, जिनमें अशरफ और अलजाफ दोनों ही शामिल थे, में ही डाल कर, मुसलमानों की गणना की गई। गुज्जरों ने इसका



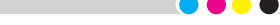
विरोध भी किया और यह आरोप भी लगाया कि गुज्जरों की गणना मुसलमानों में कर, उनकी पहचान को समाप्त करने का परोक्ष षड्यन्त्र है। जनगणना विभाग की रपटों के अनुसार जम्मू कश्मीर में गुज्जर-बकरवालों की संख्या घटती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अधिकांश बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि गुज्जरों की संख्या कम होते जाने का कारण जनगणना का तरीका है। गणना, बोली जानी वाली भाषा के आधार पर की जाती है। अनेक बार मुकामी गुज्जर, जो अपनी बोलचाल की गोजरी भाषा को प्रयोग में नहीं लाते, वे अपनी बोलचाल की भाषा को ही मातृभाषा लिखवा देते हैं। इसलिए प्रदेश में गुज्जरों की सही संख्या जानने के लिए, उनकी गुज्जर के नाते गणना करनी पड़ेगी, मजहब के नाम पर नहीं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर समुदाय की संख्या कम होने का एक दूसरा कारण पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जम्मू के कई स्थानों मसलन मीरपुर, कोटली, भिम्बर पर बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है। इन क्षेत्रों में गुज्जरों की काफी बड़ी संख्या है। लेकिन पाकिस्तान में होने के कारण उनकी गिनती हो नहीं पाती। अशरफ समाज गुज्जरों को अलजाफ श्रेणी में रखता है, इसलिए भी बहुत से मुकामी गुज्जर अपनी जनगणना में अपनी पहचान छिपा लेते हैं। जनसांख्यिकी में रुचि रखने वाले गुज्जरों की जनसंख्या प्रदेश की कुल आबादी का 10 फीसद तक भी मानते हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में शासकीय स्तर पर गुज्जर जनजाति श्रेणी में नहीं माने जाते। देश में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें उन्हें जनजाति श्रेणी में माना जाता है और इसी श्रेणी में उनके लिए नौकरियों और विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाता है। इस विषय में एक रुचिकर किस्सा स्मरण में आता है। राजस्थान में भी गुज्जर जनजाति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष व आन्दोलन करते रहते हैं। वहां दौसा क्षेत्र में गुज्जरों की काफी



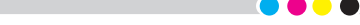
संख्या है। पुनर्सीमांकन में लोकसभा की दौसा सीट जनजाति समाज के लिए आरक्षित हो गई। इसलिए 2009 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गुज्जर समाज के लिए संकट खड़ा हो गया। राजस्थान में मीणा समाज की गणना जनजाति में होती है। इसलिए अब दौसा से गुज्जर तो लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी हो ही नहीं सकता था। गुज्जर समाज उस प्रदेश की तलाश करने लगा, जहां गुज्जर को एसटी का दर्जा मिला हुआ हो। उनकी खोज जम्मू कश्मीर पर आकर खत्म हुई। उन्होंने राजौरी के एक गांव से मोहम्मद कुमर रब्बानी चेची को तैयार किया और उसे दौसा से मैदान में उतार दिया। विरोधी प्रत्याशी ने इसका उपहास उड़ाया। दौसा में गुज्जर समुदाय का मजहब इस्लाम नहीं है। यहां के गुज्जर मुगलों के शासन में भी मतान्तरित नहीं हुए थे। अतः क्षेत्र में चर्चा होने लगी कि इस मुसलमान गुज्जर को कौन वोट देगा? लेकिन गुज्जर समुदाय की मजहब की



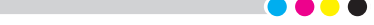
पहचान गौण हो गई। गुज्जर की पहचान उभर आई। रैली में लोग नारा लगाते हैं भागवान देव नारायण की जय। देव नारायण गुज्जरों के देवता माने जाते हैं। चेची उनसे भी ऊंची जय बोलते हैं। चेची दौसा के गुज्जरों को बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर भी बरसों पहले राजस्थान से ही गए थे। इसलिए हमारे रीति रिवाज आज भी एक जैसे ही हैं। चेची ठीक कह रहे थे। आज भी कश्मीर के गुज्जरों के रीति रिवाज कश्मीरियों से उतने नहीं मिलते जितने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले गुज्जरों से। चेची चुनाव हारे या जीते यह प्रश्न नहीं है। उन्होंने एक बार फिर गुज्जर समुदाय की राष्ट्रीय पहचान स्थापित की। गुज्जर जन समुदाय की भाषा गोजरी है। अधिकांश गुज्जर इसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन जो गुज्जर पंजाब में बस गए हैं, उन्होंने धीरे धीरे वहां की स्थानीय भाषा पंजाबी को अपना लिया है और वे आम बोलचाल में उसी



भाषा का प्रयोग करते हैं। जो गुज्जर घुमक्कड़ वृत्ति छोड़ कर कहीं भी स्थायी रूप से बस गए हैं और खेतीबाड़ी करने लगे हैं, उन्होंने गोजरी छोड़ कर वहां की स्थानीय भाषा को ही स्वीकार कर लिया है। हिमाचल में चम्बा के गुज्जर आम बोलचाल में गोजरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने गोजरी को प्रदेश की राज्य भाषाओं में शामिल किया हुआ है। गोजरी को अन्य भाषाओं के साथ राज भाषा का दर्जा देने वाला जम्मू कश्मीर शायद देश का पहला राज्य है। गोजरी भारोपीय परिवार की भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में, वहां के शासन ने कश्मीरी भाषा के साथ साथ गोजरी भाषा की लिपि भी अनिवार्य रूप से अरबी लिपि ही कर दी है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड गोजरी भाषा की किताबें अरबी लिपि में प्रकाशित करता है। जम्मू में कर गुज्जर



संस्थाएं इसका विरोध भी कर रही हैं। स्थान के अनुसार गोजरी भाषा का स्वरूप भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है। लारेंस, गोजरी भाषा को हिन्दकी कहता है। हिन्दकी खैबर पख्तूनखवा में भी बोली जाती है। ग्रियसन ने अपने भाषायी सर्वेक्षण में गोजरी को पहाड़ी ही लिखा है। लेकिन यह सही नहीं है। दरअसल गोजरी भाषा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की भाषा से अधिकांशतः मिलती जुलती है। गोजरी को इसीलिए राजस्थानी भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की जनगणना में गुज्जरों की भाषा को इसीलिए राजस्थानी कहा गया है। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने गोजरी भाषा में तथा गुज्जर इतिहास व संस्कृति में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हिन्दकी गोजरी भाषा का ही दूसरा नाम है, लेकिन पोठोहारी की उन्नति और सार संभाल के लिए कुछ किया जाना लाजिमी है। पाकिस्तान में सरायकी भाषा को लेकर पिछले लम्बे अरसे से आन्दोलन चल रहा है। मुलतान और उसके आसपास का क्षेत्र सरायकी भाषा बोलता है। लेकिन पाकिस्तान सरकार सरायकी को भाषा के आधार पर मान्यता ही नहीं देती। दरअसल पाकिस्तान सरकार वहां की स्थानीय भाषाओं को समाप्त करने का प्रयास करती रहती है। क्योंकि भाषाएं पाकिस्तान के लोगों को याद दिलाती रहती हैं कि मूलतः उनकी सांस्कृतिक जड़ें एक ही हैं। विभाजन, मजहब की आड़ में अरब, तुर्क व मुगल मूल के विदेशी मुसलमानों की साजिश थी। यह साजिश पक्के तौर पर कभी सफल हो सकती है यदि वहां की भाषाओं को समाप्त किया जाए। सरायकी को इसीलिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में यही स्थिति गोजरी की है।



अगर आपके पास भी एक ऑटोमैटिक कार है या फिर आप निकट भविष्य में ऐसी कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 5 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। कई लोग फ्यूल बचाने के लिए ढलान पर गाड़ी आते ही एकदम से गियर न्यूट्रल कर देते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा करना कार के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है।

नई दिल्ली। बेहतरीन कम्फर्ट और उपयोग में आसानी के कारण Automatic Cars भारत में काफी लोकप्रिय हो गई हैं। अगर आपके पास भी एक ऑटोमैटिक कार है या फिर आप निकट भविष्य में ऐसी कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 5 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

ड्राइविंग के दौरान गियर न्यूट्रल न करें

कई लोग फ्यूल बचाने के लिए ढलान पर गाड़ी आते ही एकदम से गियर न्यूट्रल कर देते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा करना कार के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। इंजन के गियरबॉक्स की लाइफ अच्छी रखने के लिए आप ऐसा न करें।

गियर शिफ्टर पर हाथ न रखें

गियर शिफ्टर पर अपना हाथ रखने से ट्रांसमिशन में अनावश्यक टूट-फूट हो सकती है और फिर इसकी मरम्मत काफी महंगी पड़ सकती है। गियर शिफ्टर को केवल तभी छूना चाहिए जब आप गियर बदल रहे हों। इसलिए, दोनों हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखें और गियर शिफ्टर पर अपना हाथ रखने से बचें।

कार आगे-पीछे करते समय गियर शिफ्ट न करें

मैनुअल कार के विपरीत ऑटोमैटिक गाड़ी चलाते समय गियर बदलना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जब कार आगे या पीछे चल रही हो तो कुछ डाइवर गलती से गियर बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे ट्रांसमिशन को नुकसान हो सकता है। इसलिए, हमेशा गियर बदलने से पहले पूरी तरह रुकना सुनिश्चित करें। हमेशा याद रखें कि ऑटोमैटिक कार में गियर तभी बदलें जब वाहन पूरी तरह से रुक जाए।

एक्सेलेरेटर और ब्रेक पैडल का एक साथ उपयोग न करें

एक ही समय में एक्सेलेरेटर और ब्रेक पैडल का उपयोग करना ब्रेक और ट्रांसमिशन दोनों के लिए नुकसान दायक हो सकता है। इसको रेराइडिंग द ब्रेकर भी कहा जाता है। इससे फ्यूल एफिशियंसी भी कम हो सकती है और कार के ब्रेक ज्यादा गरम होकर जल्दी खराब हो सकते हैं।

रेगुलर मंटेनेंस करते रहें

ऑटोमैटिक कार के इंजन की लंबी उम्र रखने के लिए रेगुलर मंटेनेंस जरूरी है। आपको बता दें कि ऑटोमैटिक कार को चलाना आसान है, लेकिन उसको मंटेन करके रखना उतना ही मुश्किल। इन टिप्स को फॉलो करके आप ऑटोमैटिक कार से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग कर सकते हैं।

ऑटोमैटिक कार चलाते समय कभी न करें ये पांच गलतियां, सीधे इंजन पर पड़ता है असर



कार चलाते समय ये 5 गलतियां कभी न करें

ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-5 ईवी ब्रांड पिछले महीने बेचीं इतनी इलेक्ट्रिक कारें

इस साल इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के लिए स्वच्छ और हरित परिवहन भविष्य बनाने के लक्ष्य के साथ चार पहिया वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ यह तेजी पर है। हालांकि, अगस्त 2023 में इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों की बिक्री में काफी गिरावट आई। इस सेगमेंट में पिछले महीने की तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगस्त 2023 में किन वाहन निर्माताओं ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की।

Tata Nexon EV Facelift

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2023 में भी मार्केट लीडर की स्थिति बरकरार रखी। उसके बाद एमजी मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्थान रहा। यानी टॉप-3 पोजिशन पहले की तरह बरकरार हैं। इस बीच, ह्यूंदै मोटर्स और पीसीए ऑटोमोबाइल्स ने क्रमशः चौथी और पांचवीं पोजिशन हासिल की।

Tata Tiago EV

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अलग प्लेटफॉर्म Tata.ev की शुरुआत की है। इसके तहत कंपनी अपनी तीन इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है। जिनके साथ पिछले महीने टाटा मोटर्स ने 4,613 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की। जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।

MG Comet EV

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वाले वाहन निर्माताओं की सूची में एमजी मोटर्स दूसरे नंबर रही। अगस्त के महीने में कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों की 1,150 यूनिट्स की बिक्री करने में कामयाब रही। एमजी मोटर इस समय भारतीय बाजार में दो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है। जिनमें पहली एमजी जेडएस ईवी और दूसरी एमजी कॉमेट है, जो इस समय सबसे किरायेती इलेक्ट्रिक कार भी है।

Mahindra XUV400

इस सूची में महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरे नंबर पर रही। वाहन निर्माता ने पिछले महीने 376 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। महिंद्रा इस समय भारतीय बाजार में फिलहाल एकमात्र इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा एक्सयूवी400 की बिक्री करती है।

Hyundai Kona Electric

चौथे नंबर पर ह्यूंदै मोटर का बिज हुई। वाहन निर्माता इस समय कोना इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक एक्सयूवी बेचती है। कंपनी इन दोनों ईवी की 182 यूनिट्स की बिक्री करने में सफल रही।

eC3

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करने वाले वाहन निर्माताओं की सूची में पांचवे नंबर पर सिट्रोएन रही। अगस्त के महीने में कंपनी ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार सिट्रोएन ईसी3 की 111 यूनिट्स की बिक्री की है।



त्योहारी सीजन से पहले सस्ती हो गई ये Electric SUV , 2.3 लाख रुपये कम हुई कीमत

MG ZS EV: एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV) 3 ट्रिम लेवल-एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो में उपलब्ध है। अब इनकी कीमत क्रमशः 22.88 लाख रुपये, 24.99 लाख रुपये और 25.89 लाख रुपये है।

एमजी मोटर इंडिया ने 2020 में भारतीय बाजार में ZS EV को लॉन्च किया था। एक्सयूवी को खरीदारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। पिछले साल एमजी ने बड़े बैटरी पैक और कई नए फीचर्स के साथ फेसलिफ्टेड ZS EV पेश की थी। अब 100वीं सालगिरह का जश्न मनाते हुए एमजी मोटर इंडिया ने ZS EV की कीमतों में कटौती की है। एमजी जेडएस ईवी की कीमतों में 2.3 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। यह इलेक्ट्रिक एक्सयूवी 3 ट्रिम लेवल-एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो में उपलब्ध है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत अब 22.88 लाख रुपये हो गई है, जो पहले से 50,000 रुपये कम है।

कीमत
वहीं, MG ZS EV एक्सक्लूसिव वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, जो 2.3 लाख रुपये की है। इस वेरिएंट की कीमत अब 24.99 लाख

रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। एमजी ने टॉप-स्पेक एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट की कीमत में 2 लाख रुपये की कटौती की है, जिससे इसकी कीमत 25.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो ट्रिम्स को आइकॉनिक आइवरी इंटीरियर फिनिश विकल्प के साथ पेश किया गया है।
ADAS सेलैस
गौरतलब है कि ZS EV में ADAS लेवल-2 भी आता है। ADAS तकनीक के तहत स्पीड असिस्ट सिस्टम, लेन फ्रैक्शन, रियर-ड्राइव असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और फ्रंट कोलिजन वार्निंग सहित और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं। एक प्रेस नोट में एमजी ने कहा, भारत में लॉन्च के बाद से इलेक्ट्रिक एक्सयूवी 25 करोड़ किलोमीटर से अधिक चल चुकी (सभी बिक्री हुई एक्सयूवी) है और CO2 उत्सर्जन में लगभग तीन करोड़ किलोग्राम बचाया गया है।
बैटरी और रेंज
MG ZS EV में 50.3kWh बैटरी पैक और फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। इलेक्ट्रिक मोटर 174bhp और 280Nm जनरेट करती है। दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 461 किमी की रेंज दे सकती है। ZS EV का मुकाबला Hyundai Kona EV, Tata Nexon EV और Mahindra XUV400 से है।





ईपीएफओ की सदस्य की संख्या में बढ़त, अगस्त में 16.99 लाख
ईपीएफओ से जुड़े
हर महीने ईपीएफओ में नए मंभर की सदस्यों की आंकड़ों को लेकर पेरोल डेटा जारी होता है। इस डेटा के अनुसार अगस्त महीने में 16.99 लाख नए मंभर ईपीएफओ से जुडे थे। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के नए मंभर को लेकर बयान दिया। मंत्रालय द्वारा कहा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कई कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं।

नई दिल्ली। ईपीएफओ ने अगस्त महीने का Payroll Data जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार अगस्त 2023 में ईपीएफओ से 16.99 लाख नए मंभर जुड़े हैं। ईपीएफओ के नए मंभर को लेकर श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पेरोल डेटा की साल-दर-साल तुलना पिछले वर्ष अगस्त 2022 की तुलना में नए मंभर शुद्ध सदस्यों में मामूली वृद्धि को दर्शाती है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि अगस्त महीने के दौरान 3,210 प्रतिष्ठानों ने अपना पहला ईसीआर जमा किया। इससे कर्मचारियों को ईपीएफओ का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ाया।
पेरोल डाटा के आंकड़े
पेरोल डेटा के अनुसार अगस्त 2023 के दौरान लगभग 9.26 लाख नए सदस्यों ने नार्माकन किया है। इसमें 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के नए सदस्य शामिल हैं। यह अगस्त में कुल नए सदस्यों का 58.36 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि पहली बार नौकरी तलाशने वाले अधिकांश युवा बड़ी संख्या में हैं।
इसके अलावा पेरोल डेटा दर्शाता है कि लगभग 11.88 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर चले गए और फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए। जो कि पिछले साल अगस्त 2022 की तुलना में 10.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
इन सदस्यों ने अपनी नौकरियां बदल लीं और ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए। इसी के साथ इन्होंने ईपीएफओ फंड से निकासी के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी जमा राशि को स्थानांतरित करने का ऑप्शन चुना। इसके अलावा पिछले दो महीनों में ईपीएफओ से बाहर निकलने वाले सदस्यों में लगातार गिरावट आई है।
पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि अगस्त महीने के दौरान जोड़े गए कुल 9.26 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2.44 लाख महिला सदस्य हैं, जो पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुई हैं। वहीं, सबसे ज्यादा मंभर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात से जुड़े हैं।

भावी पीढ़ी पर नहीं डालेंगे कर्ज का बोझ, सरकार उठा रही है कई कदम: वित्त मंत्री

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में संबोधन देते हुए कहा कि देश में बढ़ते कर्ज एक चिंता का विषय है। सरकार आगामी पीढ़ी पर कर्ज चुकाने का बोझ नहीं डालेगी। इसके लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से राज्य सरकार पर लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने देश पर कर्ज के स्तर को बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली। कोरोना काल के बाद के दो वित्त वर्षों में देश पर बढ़ते कर्ज के बोझ की चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार आगामी पीढ़ी पर कर्ज चुकाने का बोझ नहीं डालेगी। हालांकि यह काम किस तरह से किया जाएगा, इसको वह साफ तौर पर नहीं बता सकी। गुरुवार को कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राजकोषीय घाटा प्रबंधन को लेकर बहुत ही गंभीर है।

सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि कर्ज चुकाने का बोझ अगली पीढ़ी पर नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि हम कई ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिससे कर्ज को आगे चल कर कम किया जा सके। वित्त मंत्री का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से राज्य सरकार पर लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने देश पर कर्ज के स्तर को बढ़ा दिया है।

सीतारमण ने इस बारे में कहा कि
हम राजकोषीय स्थिरता को लेकर बेहद गंभीर हैं और वित्तीय प्रबंधन को लेकर हम कोई भी फैसला करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि भविष्य की पीढ़ी पर कोई बोझ नहीं डाला जाए। यह बहुत ही आसान है कि जो अभी कर्ज है उसका पूरा बोझ आने वाली पीढ़ी पर डाल दिया जाए। वैसे दूसरे देशों के मुकाबले भारत पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा नहीं है इसके बावजूद हम दूसरे देशों में कर्ज के स्तर का अध्ययन कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि दूसरे देश कर्ज का प्रबंधन किस तरह से कर रहे हैं।'

इसके आगे वह कहती है कि देश की विकास की जरूरत को देखते हुए बाहर से कर्ज लेने की जरूरत भी है लेकिन इसका उपयोग हमेशा जिम्मेदारी से होनी चाहिए। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा कर्ज कोरोना महामारी के पहले साल 2020-21 में लेना पड़ा



था। वह यह भी कहती है कि कोरोना काल में हमने जो कर्ज लिया था उसका इस्तेमाल जनता के हाथ में सीधे पैसा देने की जगह हमने एक-एक पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक संपत्ति स्थापित

करने में किया ताकि बेहतर उपयोग हो।
देश पर कितना है कर्ज
जहां तक देश पर कर्ज की बात है तो सितंबर, 2023 में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट बताती है कि मार्च,

2023 तक भारत कुल 624.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। पिछले वित्त वर्ष विदेशी कर्ज में सिर्फ 0.9 फीसद की वृद्धि हुई थी। कुल जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का स्तर

मार्च, 2022 में 20 फीसद के करीब था जो अब घट कर 18.9 फीसद पर आ गया है। जून, 2023 में कुल विदेशी कर्ज की राशि 629 अरब डॉलर की रही थी।

2,000 रुपये के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर ने दिया अपडेट, सिस्टम में बचे हैं केवल 10,000 करोड़ रुपये

19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करना का एलान किया था। इस एलान में आरबीआई ने कहा था कि यह नोट बाकी नोटों की तुलना में कम चलन में हैं। इस वजह से यह कदम उठाया गया था। आरबीआई ने नोटों को डिपॉजिट करने या फिर एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। बाद में इस समयसीमा को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 2,000 रुपये के अधिकतम नोट कर्कुलेशन में वापस आ गए हैं। वह यह भी बताते हैं कि केवल 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अभी भी लोगों के पास हैं। इन नोटों को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि यह नोट भी जल्द वापस हो जाएंगे या फिर जमा हो जाएंगे।

आरबीआई गवर्नर ने एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा कि 2,000 रुपये के नोट वापस आ रहे हैं और सिस्टम में केवल 10,000 करोड़ रुपये बचे हैं। उम्मीद है कि यह राशि भी वापस आ जाएगी।

अक्टूबर महीने की शुरुआत में शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2,000 रुपये



के 87 प्रतिशत नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं। वहीं बाकी नोटों को काउंटर में एक्सचेंज या जमा किया जा रहा है।

2,000 रुपये के नोट को चलन से किया गया बाहर

19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का एलान किया था। 2,000 रुपये के नोट को बदलने या फिर जमा करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक

का समय दिया गया था। इसके साथ ही 30 सितंबर 2023 तक नोटों को वैध रखा गया था। आरबीआई ने बाद में 7 सितंबर 2023 तक नोट बदलने या फिर एक्सचेंज करने का समय दिया था।

8 अक्टूबर से भारतीय रिजर्व बैंक के 19 स्थानों पर नोट को एक्सेचेंज किया जा सकता था। आरबीआई के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के बैंक नोट बदल सकते हैं। हालांकि,

बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा कराने के लिए कुल राशि की कोई सीमा नहीं है।

2016 में हुई थी नोटबंदी
वर्ष 2016 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को अमान्य करने का एलान किया था। इन नोटों को लेकर आरबीआई ने बताया कि यह नोट लगभग 88 प्रतिशत से अधिक सिस्टम में वापस आ गए हैं।

बैंकिंग सेक्टर में पिछले 9 साल के अंदर हुआ जबरदस्त डेवलपमेंट, एसबीआई ने रिपोर्ट में किए कई खुलासे

बैंकिंग सेक्टर के कारोबार में 63 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उससे अधिक विकास पिछले 9 वर्षों में हुआ है। ये खुलासा एसबीआई की एक रिपोर्ट में किया गया है। मार्च 2014 से लेकर वर्ष 2023 के मार्च तक बैंकों ने ऋण देने व जमा लेने के मद में 187 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। बैंकिंग सेक्टर के कारोबार में 63 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उससे अधिक विकास पिछले 9 वर्षों में हुआ है। ये खुलासा एसबीआई की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1951 से लेकर मार्च, 2014 तक बैंकों ने 142 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसमें ऋण देने से लेकर जमा लेने का कारोबार शामिल है।

बैंकों ने किया 187 लाख करोड़ रुपये का कारोबार
मार्च 2014 से लेकर वर्ष 2023 के मार्च

तक बैंकों ने ऋण देने व जमा लेने के मद में 187 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया। यानी कि बैंकों ने पिछले नौ साल में गत 63 सालों के मुकाबले 1.3 गुना अधिक कारोबार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर के विकास से यह पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी की ओर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर की स्थिति मजबूत होती जा रही है और अब असुरक्षित लोन भी कम होते जा रहे हैं।

पहले के मुकाबले लिया जा रहा ज्यादा कर्ज

मैयूफैकचरिंग सेक्टर के उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी से बैंकों से पहले के मुकाबले अधिक कर्ज लिए जा रहे हैं। वर्ष 2022 से बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022 से लेकर इस साल सितंबर तक बैंकों में होने वाले डिपॉजिट में 13.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही जबकि बैंकों के लोन में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी है।

त्योहारी सीजन पर बढ़ेगी मांग
त्योहारी सीजन की वजह से अभी कर्ज की



मांग में तेजी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 98 प्रतिशत पर्सनल लोन 50,000 रुपए या इससे अधिक रकम के होते हैं। सिर्फ दो प्रतिशत

लोन ही 50,000 रुपए से कम वाले होते हैं और ये दो प्रतिशत वाले लोन ही अधिक असुरक्षित होते हैं। पर्सनल लोन में सबसे

अधिक हिस्सेदारी हाउसिंग और ऑटो की है और दोनों ही लोन की अवधि बड़ी होती है और ये सुरक्षित लोन माने जाते हैं।

कई हफ्तों की गिरावट के बाद Forex Reserves में बढ़त, 13 अक्टूबर तक 1.153 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा

लगातार कुछ कारोबारी हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी थी। वहीं आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक के अनुसार 13 अक्टूबर 2023 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.153 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 585.895 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी के साथ सोने के भंडार में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी किया है। पिछले कई

हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिला था। 13 अक्टूबर 2023 को समाप्त कारोबारी हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 1.153 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 585.895 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का कुल भंडार 2.166 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 584.742 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।

भारतीय रिजर्व ने बताया कि अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा निधि 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

वहीं, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने पिछले साल से वैश्विक विकास के कारण दबाव के बीच रुपये की रक्षा के लिए रिजर्व तैनात किया था।

विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े
आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक के अनुसार 13 अक्टूबर से पहले के हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 519.351 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं, डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी करेंसी ने भी विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित किया है।

सोने के भंडार में भी बढ़त
आरबीआई ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 1.268 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 43.575 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 17.995 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए।

आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 4.975 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।



